# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

## दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

---

## शुभ्रांशु के खुले खतों का जवाब

### 23 मार्च को प्रस्तावित बस्तर से दिल्ली बाइक रैली

### बस्तरवासियों को भटकाने के शुभ्रांशुजी की एक और नाकाम कोशिश

शुभ्रांशुजी कुछ सत्यों, कुछेक अर्ध सत्यों और असत्यों का पुलिंदा लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), उसके नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन पर कीचड़ उछालने के लिए समय–समय पर अखबारों व सोशल मीडिया में लेख या पार्टी के नाम खुले पत्र लिखते रहते हैं. हां, वो एक बात अवश्य सच लिखते हैं कि मेरा उनसे रायपुर के कॉफी हाउज में 1990 में पहला परिचय हुआ था. वह परिचय मित्रता में, रायपुर से दिल्ली तक फैल गया था. हालांकि वह वैचारिक मित्रता में तब्दील नहीं हो पाया. या हो सकता है, वो हमारे बीच के संबंध को मित्रता से ज्यादा स्रोत समझे हों. इस संबंध में भी कुछ कहना तो है, लेकिन फिर कभी.

बहरहाल, अलग–अलग वर्गों व तबकों के लोग एक तरफ अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन की राह पर हैं तो शुभ्रांशु उनके आंदोलनों का समर्थन करने के बजाए, सरकारों के एजेंडे को लेकर यात्राओं के आयोजन में लगे हैं. ज्वलंत एवं जनता के जीवन–मरण की समस्याओं के बारे में वे कभी मुंह नहीं खोलते हैं. सरकारों के लिए असुविधाजनक सवाल वे कभी उठाते नहीं, न ही वैसी मांगें रखते हैं. शोषक–शासक वर्गों की शाबासी पाने लायक मुद्दों को ही लेकर वे कभी साइकल रैली, कभी पदयात्रा, फिर कभी बाइक रैली का आयोजन करते हैं. जनविरोधी, पार्टी विरोधी चरित्र के एवं शोषक वर्गों के लोगों को छोड़कर, कुछ समय के लिए, एकाध बार के लिए वे कुछेक लोगों को भ्रमित कर सकते हैं लेकिन शोषित–शासित लोगों को लंबे समय तक भ्रमित कर वे अपने नाजायज इरादों में सफल नहीं हो सकते हैं.

अपनी तथाकथित शांति प्रक्रिया के चौथे प्रयास के रूप में शुभ्रांशुजी 23 मार्च को बस्तर से शुरू कर दिल्ली तक बाइक रैली निकालने की घोषणा कर चुके हैं जोकि बस्तर की जनता को क्रांतिकारी आंदोलन के रास्ते से भटकाने की एक और नाकाम कोशिश के अलावा कुछ नहीं है. चूंकि उनकी बाइक रैली मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, कर्मचारियों, शिक्षाकों, छोटे दुकानदारों जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, का ध्यान उनकी वास्तविक समस्याओं से बंटाने के लिए प्रस्तावित है, इसलिए उसका विरोध व बहिष्कार करना चाहिए. उससे दूर रहेने तद्वारा उसे विफल करने की सख्त आवश्यकता है.

शुभ्रांशुजी एक ओर अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ, भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए मुस्कराते हुए फांसी पर झूलने वाले महान क्रांतिकारी शहीद योद्धा कॉमरेड्स भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की 90वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर उक्त रैली शुरू कर रहे हैं तो दूसरी ओर आज के माओवादी क्रांतिकारियों जो भगत सिंह की विरासत को ऊंचा उठाए हुए हैं और देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व बड़े भूस्वामियों के (साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति एवं सामंती वर्गों) के खिलाफ एवं नवजनवादी भारत की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष–जनयुद्ध संचालित कर रहे हैं, को हिंसावादी करार दे रहे हैं. यह सरासर भगत सिंह एवं उनके साथियों का अपमान ही नहीं, उनके आशयों, लक्ष्यों, रास्ते से लोगों को भटकाने की कोशिश भी है जिसका पर्दाफाश करने हमारी पार्टी बस्तर, छत्तीसगढ़ सहित देश के नवजवानों व छात्राओं–छात्रों का आह्वान करती है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि भगत सिंह एवं उनके साथी क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि वे एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी का शोषण न हो, ऐसे समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए क्रांति का आवाहन कर रहे थे. उनका उद्देश्य सिर्फ गोरों के खिलाफ लड़ना ही नहीं था, बल्कि शोषकों के खिलाफ था चाहे वे काले पूंजीपति भी क्यों न हो.

शुभ्रांशुजी स्वयं को बस्तर के आदिवासियों के हितचिंतक, उनके अमन–चैन के हिमायती साबित करने अपने लेखों व पत्रों के जरिए एड़ी–चोटी का जोर लगाते हैं. उनके अब तक की शांति प्रक्रिया में उन्होंने कभी सरकारों से यह मांग नहीं की कि बस्तर में नरसंहार बंद किया जाए जिसे देशव्यापी समर्थन हासिल है, सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा आदिवासियों की झूठी मुठभेड़ हत्याएं बंद किया जाए, शुभ्रांशु जिस संवेधानिक अधिकारों की वकालत करते हैं, उनमें से एक पेसा कानून के तहत ग्रामसभाओं के अधिकारों का घोर उल्लंघन करते हुए

लगातार बैठाए जा रहे पुलिस कैंपों, सड़कों, ब्रिजों जिनके खिलाफ विगत 2 सालों से लाखों आदिवासी जनता अहिंसात्मक(शुभ्रांशुजी का प्रिय तरीका) आंदोलन कर रहे हैं, को बंद किया जाए, नए बैठाए गए पुलिस कैंपों के आस–पास के गांवों की महिलाओं पर जारी यौन हिंसा, अत्याचार बंद किए जाए, सारकेनगुडा, टीएमटीडी, एड्समेट्टा नरसंहारों, गृहदहन के मामलों में सरकारी जांच आयोगों की सिफारिशों पर फौरन अमल किया जाए, पिछले मई से जारी सिलंगेर आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा किया जाए जिन्हें छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस छोड़ राज्य के सभी संसदीय राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, छात्रो–नवजवानों, मानवाधिकार संगठनों, आदिवासी, गैर–आदिवासी सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडियाकर्मियों सहित देश भर के लोगों का जबर्दस्त समर्थन प्राप्त है. यहां अखबारों व टीवी चैनलों की इन खबरों के बारे में बताना वाजिब होगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों पर नाहोड, पूसनार–बुर्गी में पुलिस व अर्ध–सैनिक बलों ने हमले कर धरनारत लोगों की बेदम पिटाई की, धरना पंडालों को जलाकर राख कर दिया गया, उनके खान–पान की सामग्री को नष्ट कर दिया गया था. सोशल मीडिया में सदा सक्रिय रहने वाले शुभ्रांशुजी की नजर में ये खबरें नहीं आयीं, न ही उनके सीजी नेट स्वरा को इन आंदोलनकारियों की आवाजें नहीं मिलती हैं. उन्होंने कभी मजदूर विरोधी 4 श्रम कोडों, देशविरोधी तीन किसान कानूनों, विद्युत बिल–2020 को रद्द करने व फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग का समर्थन नहीं किया. क्या ये सब हमारे जनयुद्ध की जायजता को बार–बार प्रकट नहीं कर रही हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि जनसेना और जनयुद्ध के बिना जनता के हाथ कुछ लगेगा नहीं.

साथ ही शुभ्रांशुजी हमेशा यह कहने से नहीं चूकते कि माओवादी अपने नवजनवादी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने बस्तर के आदिवासियों को इस्तेमाल कर रहे हैं. वे माओवादियों को यह भी सुझाव देते हैं कि अब सरकार से वार्ता करके संवैधानिक अधिकारों के जरिए, 6वीं अनुसूची को लागू करवाने के जरिए वे आदिवासियों का कर्ज चुकाएं. माओवादी अब हिंसा का रास्ता छोड़ चुनाव में शामिल हो जाएं. वे इस 'आशा' व 'विश्वास' के साथ यह भी हमेशा कहते हैं कि अब माओवादी हारने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं.

यहां शुभ्रांशुजी की शांति प्रक्रिया का सवाल हिंसा और अहिंसा का कतई नहीं है. उनके द्वारा अहिंसा की वकालत भी कोई शांति या शांति वार्ता का मामला नहीं है. यह वर्ग हितों के बीच टकराव का सवाल है. सत्ताधारी वर्गों द्वारा अपने शासन और शोषण को बरकरार रखने का सवाल है. उसके खिलाफ उठने वाली आवाज को राज्ययंत्र द्वारा दमन करने का सवाल है. शोषित–शासित वर्गों द्वारा शोषण से दमनकारी शासन से छुटकारा पाने का सवाल है. उस हेतु हथियारबंद लड़ाई का सवाल है. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा संचालित वर्ग संघर्ष–जनयुद्ध/छापामार युद्ध उसी का हिस्सा है. वह चार वर्गों – मजदूरों, किसानों(जमींदारों को छोड़), छोटे पूंजीपतियों व राष्ट्रीय पूंजीपतियों जिनका बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी साम्राज्यवादियों से कोई सांठगांठ न हो, के संयुक्त मोर्चा जिसमें सभी उत्पीड़ित विशेष सामाजिक तबकों – दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं – के लोग भी शामिल हों, बनाकर, उसका नेतृत्व कर देश में नवजनवादी राज्यसत्ता स्थापित करेगी जिसमें आदिवासियों को उनके इलाकों पर शासन करने की स्वायत्तता दी जाएगी. शुभ्रांशु माओवादी पार्टी को आदिवासियों से अलग दिखाने/करने की विफल कोशिश में रहते हैं. भारत के संविधान में जो स्वायत्तता 6वीं अनुसूची के तहत है, वह नाममात्र की है. पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां वह लागू है, उसका क्या हश्र हो रहा है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून(आफ्स्पा–एएफएसपीए) वहां लोगों का कत्लेआम कैसे कर रहा है; संविधान की पांचवी अनुसूची, पेसा के तहत ग्राम सभाओं के अधिकारों का किस तरह घोर उल्लंघन हो रहा है, जिसका जीता–जागता उदाहरण के तौर पर बस्तर हमारे सामने है; सभी को विदित है. क्या शुभ्रांशु इन सबसे वाकिफ नहीं हैं? बात दरअसल यह है कि वे अपना पक्ष तय कर चुके हैं. शोषक–शासकों का पक्ष. चोला पहने हैं, शांति का. शांति के नाम पर लोगों को विद्रोह से दूर करना, लड़ाई से भटकाना, ज्ञापन, रैलियों, सभा–सम्मेलनों तक सीमित करना, खासकर सशस्त्र संघर्ष की राह से भटकाना; दूसरी ओर शांति के नाम पर शासकों – तीन शोषक वर्गों प्रचलित भाषा में कहा जाए तो देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों व बड़े भूस्वामियों की हिंसा व लूट का शिकार बना देना. शुभ्रांशुजी की हिंसा–अहिंसा और शांति प्रक्रिया का असली मतलब व मकसद यही है. इसके सिवाय और कुछ नहीं.

जहां तक दोनों तेलुगु राज्यों – तेलंगाना, आंध्र प्रदेश – में बसे सलवा जुडुम विस्थापितों को वहां की सरकारों द्वारा बेदखल करने का सवाल है, सबसे पहले शुभ्रांशुजी इस सच्चाई को झुठलाने की कोशिश न करें कि विस्थापितों में अधिकांश सलवाजुडुम पीड़ित हैं जिनके गांव–घर, संपत्ति जला दी गयी थी, जिनके परिवार के सदस्यों, रिश्ते–नातेदारों की पुलिस द्वारा हत्या की गयी. यदि कोई यह कह रहे हैं कि माओवादियों के भय से भाग गए हैं, उसमें दो बातें हैं. एक है, पुनरावास मिलने की आशा. दूसरा है, सलवा जुडुम कार्यकर्ता या गुंडे

बनकर जनविरोधी कार्यों में संलग्नता. हमारी पार्टी ने तो सलवा जुडुम शिविरों की जनता से भी गांवों में वापस आकर रहने की अपील की थी. उन्हें गांवों में वापस बसाया गया था, उन्हें उनकी जमीनें दी गयी थी. जहां तक दोनों तरफ की हिंसा के शुभ्रांशु की बात है या कुछेक पत्रकारों का एकतरफा लेखन के मुताबिक माओवादियों के डर की वजह से तेलुगु राज्यों में पलायन करने की बात है, वह हमारे खिलाफ सरकारी दुष्प्रचार का हिस्सा मात्र है. इसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है. इस बात पर आप जानबूझकर परदा डाल रहे हैं कि दोनों तेलुगु राज्यों की सरकारें अब आदिवासियों/मूलवासियों की जमीनों को पौधारोपण, 'हरिताहारम' आदि योजनाओं के नाम पर हड़प रही हैं जिसके खिलाफ एवं अपनी झूम खेती की जमीनों को बचाने आदिवासी जनता आंदोलनरत है. शुभ्रांशु यह मानने के लिए कह रहे हैं कि दफ्तर के एक बाबू की गलती से गुत्ति कोया की जगह गुत्ता कोया शब्द रिकॉर्डों में अंकित हुआ है जिसकी वजह से उन्हें गैर–आदिवासी मानकर बेदखल किया जा रहा है. यह बचकाना कोशिश है. अक्षर गलती को सुधारा जा सकता है, आदिवासियों को वनाधिकार कानून के मुताबिक जमीनों का आवंटन किया जा सकता है. ये सरकारें ऐसा कतई नहीं करने वाली हैं. शुभ्रांशु यह माने या न माने लेकिन यह एक सच्चाई है कि तेलुगु राज्यों में बसे आदिवासी कई कारणों से अब वापस छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहेंगे. उनकी समस्या आवास और जमीन की समस्या है. उन्हें वहीं जमीनें चाहिए. वे अपनी जमीनों के लिए आंदोलित हैं. हम उन्हें उनकी जमीनें दिलाने के पक्ष में हैं. हम उनके आंदोलनों का समर्थन करते हैं. आज आदिवासी हितैषियों को उस दिशा में सोचना चाहिए. शुभ्रांशुजी को उन्हें दिल्ली, रायपुर यात्राओं के नाम पर भटकाना नहीं चाहिए.

आज की दुनियावी परिस्थितियों के मद्देनजर 23 मार्च के अवसर पर यदि कोई ईमानदार व भगत सिंह का सच्चा अनुयायी या वारिस कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य शहीद भगत सिंह के दिए नारों – ''साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद'' को ऊंचा उठाना होगा. यूक्रेन पर रूसी साम्राज्यवाद के हमले का विरोध करें, पहले युद्ध को उकसाने एवं अभी यूक्रेन को हथियार आपूर्ति करते हुए युद्ध को जारी रखने तद्वारा मुनाफा सहित अपने वैश्विक प्रभुत्व के हितों के लिए की जा रही अमेरिकी साजिशों के खिलाफ, नाटो रद्द करने, युद्ध को फौरन बंद करने, युद्ध भार को आम जनता, मजदूर, किसान, मध्य वर्ग पर न डालने, सिर्फ कॉरपोरेट घरानों पर डालने, भारत सरकार को युद्ध के खिलाफ कार्य करने की मांगों को लेकर आवाज बुलंद करनी चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, पदयात्रा से लेकर साइकल, बाइक रैलियां करनी चाहिए. अन्यथा 23 मार्च और भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर शोषकों के लिए रोटी सेंकने की कवायद ही माना जाएगा. शुभ्रांशु की इस कवायद का हर तरफ से विरोध होना चाहिए.

**दिनांक–19 मार्च, 2022**

**(विकल्प)**

**प्रवक्ता**

**दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी**

(संपादक महोदय, नमस्कार. मेरे(विजय/विकल्प/वासु आदि) या हमारी पार्टी के नाम शुभ्रांशु जी के खुले खतों के लिए आपके अखबार में समय–समय पर जगह दी जाती रही. भिन्न विचारों को जनता तक पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी के तहत मैं आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखता हूं कि उनके खुले खतों का खुला जवाब भी प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे. ऐसा सनम्र निवेदन के साथ, विकल्प.)